

(लेखक इब्नू नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

संवेलेख	77,656.09 ▲ 286.98	निफ्टी	24,334.55 ▲ 115.50	सोना	₹ 1,67,100 ▲ ₹ 2,700	चांदी	₹ 2,50,000 ▼ ₹ 3,500	डालर	₹ 95.44 ▼ ₹ 0.26	कूड प्रति बैरल	\$ 89.32
---------	-----------------------	--------	-----------------------	------	-------------------------	-------	-------------------------	------	---------------------	----------------	----------

भारत-जापान बनाएंगे एआइ व सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मेक इन इंडिया से जुड़े हाईटेक उद्योग को गुणवत्ता सर्टिफिकेट से मिलेगी छूट

राजीव कुमार • जागरण

टोक्यो: ग्लोबल साउथ या कम आय वाले देशों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज (एआइ) और सेमीकंडक्टर को सप्लाई चेन तैयार करने के लिए भारत व जापान मिलकर काम करेंगे। वर्ष 2023 में इस पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है। मंगलवार को एआइ व सेमीकंडक्टर से जुड़ी जापान की करीब 20 कंपनियों ने वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष भारत में निवेश को लेकर अपनी दिग्दर्शिकाएं जमा कीं।

सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़े उपकरण बनाने वाली जापान की कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ने कहा कि भारत में निर्माण के



टोक्यो में मंगलवार को जापान-भारत सांघीय मंत्री स्तर के अग्रस्थ यासुतोशी निशिमुरा से मुलाकात करते केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व एआइ

- एआइ-सेमीकंडक्टर से जुड़ी 20 जापानी कंपनियों भारत में निवेश करेंगी
- 2032 तक 150 अरब डॉलर होगा भारत का सेमीकंडक्टर कारोबार

एमएसएमई को प्रशिक्षण देंगी जापानी कंपनियां
वाणिज्य व उद्योग मंत्री के साथ आए उद्योगियों के दल का नेतृत्व कर रहे औद्योगिक समूहन पिक्वरी के अध्यक्ष व आयोजी समूह के वाइस चेयरमैन अतक गोयुका ने बताया कि भारत और जापान की कंपनियां आधुनिकी देशों व कई अन्य मरीच देशों के लिए एक साथ मिलकर हाईटेक सेक्टर में निर्माण करने की तैयारी में हैं। इस दिशा में समन्वयन देती जा रही है। वाणिज्य मंत्री के दौर में इस पर बर्तन चल रही है कि मेन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी जापानी कंपनियां भारत के एमएसएमई को प्रशिक्षण देंगी। एआइ और सेमीकंडक्टर के सफाये रख और बिजनेस प्राप्त करने में भी जापान से सहयोग मिलेगा।

दीर्घा इस्तेमाल होने वाले पाट्स व उपकरण लाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से

सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है जो भारत में उत्पादन शुरू करने में व्यवधान का काम करता है। ऐसी

ही मांग कई अन्य जापानी कंपनियों की भी थी। इस पर वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत

आखिरी घंटे में खरीदारी और कच्चे तेल की नरमी से बड़े घरेलू शेयर बाजार

मुंबई, प्रे: आखिरी घंटे में खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते दोनो प्रमुख सूचकांक संसेखस और निफ्टी मंगलवार को दिनभर के उतार-चढ़ाव के कम करते हुए बंदत के साथ बंद होने में कामयाब हुए। दिन के दौरान अविश्वस्य साम्य गिरावट होने चाले बीएसई संसेखस अंत में 286.98 अंक की बंदत के साथ 77,656.09 पर बंद हुआ। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी दिनभर अस्थिरता के बाद अंत में 115.50 अंक की बंदत के साथ 24,334.55 पर बंद हुआ।

संसेखस में इंडियों की पेंटर कंपनी इंटरनल एक्विपमेंट, अण्णो पावर, इन्फोसिस, ट्रेड, टाइटन और एलबीओए के शेयरों में बंदतरी लगी। वहीं, जोमेटो की संयंत्राल एटलान्ट, एक्सप्लोर टेक, मेनग्रिड और जेनज फिनसर्व में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक तेल मानक ब्रेट क्रूड मंगलवार को तीन प्रतिशत गिरकर 89.32 डॉलर प्रति बैरल

268 अंक बढ़कर
77656 के स्तर
पर बंद हुआ बीएसई संसेखस

● वैश्विक तेल मानक ब्रेट क्रूड तीन प्रतिशत घटकर 89.32 डॉलर प्रति बैरल पर आया

सोने में लगातार चौथे दिन तेजी रही, चांदी में गिरावट रही

नई दिल्ली, प्रे: वैश्विक कीमतों में गिरावट के बावजूद स्थानीय स्तर पर सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई। आल इंडिया सरासरी सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई। आल इंडिया सरासरी सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई। आल इंडिया सरासरी सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई।

और मंगलवार को इस्को मूल्य में 3,500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई। आल इंडिया सरासरी सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई। आल इंडिया सरासरी सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई।

पर आ गया। शिंजो जिनट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयर प्रमुख विनोद नार्व का कहना है कि अमेरिकी की और से डर के खिलाफ लोग हुए बाहुलीकृत प्रतिक्रिया बाजार की अपेक्षाओं से कम रहे, जिससे कच्चे

तेल की कीमतों और बांड ग्रीड हाल के उच्चतम स्तरों से कम हुई। बीएसई मिडिकेन सेलेक्ट इंडेक्स में 0.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जबकि स्थानिक सेलेक्ट इंडेक्स में 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट रही।

राष्ट्रीय फलक

यूपीआइ के 10 साल: डिजिटल भुगतान यात्रा में ऐतिहासिक मील का पत्थर, पीएम ने की सराहना

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के एक दशक पूरे होने पर मोदी ने इसे भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में एक बड़ा मोड़ बताया

वोले- इसके दायरे और विशाल पैमाने पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए; अमित शाह, राजनय सिंह ने भी की सराहना



प्रतीकालक

नई दिल्ली, प्रे: यूनियनइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) ने अपनी शुरुआत के 10 सालवन पूरे कर लिया है। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा का एक प्रमुख मोड़ कर दिया है। नेगरल पेमेंटस कर्पोरेशन आफ इंडिया (एफपीसीआई) द्वारा निर्वाह का एक इंडिया (आरबीआई) के नियमावली दायरे में 25 अगस्त, 2016 को लॉन्च किया गया यूपीआइ आज देश के वित्तीय समावेशन का मुख्य आधार बन चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म 'फैस' पर पोस्ट करते हुए देशभरियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यूपीआइ के दायरे और विशाल पैमाने पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। पीएम ने नागरिकों से अपने यूपीआइ अनुभवों को साझा करने और यह बताने का आग्रह किया कि इनने उन्हें नैनिक जीवन को कैसे प्रभावित किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनय सिंह ने भी यूपीआइ के 10 वर्षों पर होने पर इसकी सराहना की सराहना की है। अमित शाह ने इसे एक तीव्र और सुरक्षित माध्यम बताया हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का परिणाम है, जिसने नवजवान के जरिये देश की विकास यात्रा को गति दी है और डिजिटल इंडिया के तहत देश को दुनिया की सबसे बड़ी

10 वर्षों में रिकार्ड तोड़ वृद्धि
यूपीआइ ने देश को एक रियल-टाइम भुगतान माध्यम प्रदान किया है। पिछले एक दशक में यूपीआइ ने अनुमूर्त वृद्धि दर्ज की है। लेनदेन की संख्या की दृष्टि से वित्त वर्ष 2016-17 के महान 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में यह 24.162 करोड़ से अधिक हो गई है, जो लगभग 13 हजार गुना की बढ़ी वृद्धि है। अगर लेनदेन के दृष्टि की बात की जाए तो इसी अवधि में लेनदेन का कुल मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो बार बार गुना से अधिक की छंवांग है। और यूपीआइ भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के सबसे सफल स्तंभों में शुमार है, जो सिंगल एप्लीकेशन के जरिये सुरक्षा और सहजता प्रदान करता है। पीएम तथा पीएम-टू नरेन्द्र मोदी ने यूपीआइ को सक्षम बनाया है।

रियल-टाइम पेमेंट प्रणाली दी है। वहीं, राजनय सिंह ने अपने संदेश में कहा कि पिछले एक दशक में यूपीआइ ने भारत के डिजिटल भुगतान परियोजनाओं को तेज कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यूपीआइ के उपयोग में गिरावट आई है, लेकिन यह बाजार में इसका अस्तित्व दिखा रही है।

नासिक की मंडियों में प्याज के भाव देशभर के लिए संकेतक

अरविद शर्मा • जागरण

नई दिल्ली: प्याज की कीमत बढ़ने की पहली आह नासिक में सुनाई देती है। इसकी वजह केवल महाराष्ट्र में बढ़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन होना नहीं है, बल्कि नासिक में उत्पादन क्षेत्र के साथ बड़ी प्याज मंडियों, आधुनिक एवं थोक कारोबारियों का नेटवर्क, वेयरहाउस और देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन भी जुड़ी हुई है। इसलिए, नासिक की मंडियों में आठक और कीमतों में बदलाव देशभर के प्याज बाजार में बढ़ते भाव का संकेत बन जाता है। मौजूदा तेजी भी इसका उद्घरण है। सोमवार को दिल्ली की मंडियों में प्याज करीब 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि नासिक में 42 और मुंबई में 35 रुपये प्रति किलोग्राम तक भाव पहुंच गया था। हालांकि सरकार की पहल के बाद मंगलवार को नासिक की मंडियों में आठक बढ़ी और भाव में नरमी का रुख दिखा।

महाराष्ट्र में देश का 60 प्रतिशत उज्जता है, जिसमें नासिक की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत होती है। नासिक में प्याज की करीब 27 बड़ी मंडियां हैं।

खुदरा बाजार में 64 रुपये प्रति किग्रा हुई चीनी

नई दिल्ली, प्रे: खुदरा बाजार में मंगलवार को चीनी की कीमत लगभग एक रुपये बढ़कर करीब 64 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं, चांदी की 76 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। चीनी की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन यह बाजार में इसका अस्तित्व दिखा रही है।

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर



अनुसूचित की मंडी में सोमवार को प्याज उतारता एक श्रमिक। एएफपी >>

इन्में लालसोनी प्रमुख है, जिसे देश की सबसे बड़ी मंडियों में गिना जाता है। पिंपलगांव बसस्टैंड, चांदवड, देवला, येसला, निमगाड, मंगमाड और उमगाणे जैसे बड़े बाजारों में किसान से उगाए खरीदकर एजेंट और कारोबार दूसरे राज्य के बाजारों तक पहुंचाते हैं। नासिक में आधुनिक एवं कारोबारियों के साथ बड़े स्तरों में वेयरहाउस हैं, जहां प्याज को महीने तक स्टोर किया जाता है। नासिक के नेटवर्क और भंडारण की सुविधा के चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कारोबार भी प्याज यहां स्टोर करते हैं। मुंबई वेंगूरला भी करीब है, जिससे निर्यात में सहूलियत होती है। कर्नाटक के प्याज का बड़ा हिस्सा भी

नासिक से ही निर्यात होता है।

सरकार ने भी जुलाई में संकेत दिया था कि नासिक में कारोबारियों का एक वर्ग स्ट्रेटजी वाली खरीद कर रहा था। इस समय देश में प्याज की उपलब्धता को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं थी और महाराष्ट्र की मंडियों में रोजाना 30 हजार टन से अधिक प्याज की आठक हो रही थी। ऐसे में बड़ी मात्रा में प्याज का तत्काल बाजार में न आना कीमत पर दबाव बढ़ा सकता है। लालसोनी जैसे बाजारों में भाव बढ़ने ही दूसरे राज्यों में यानी जिस नासिक से बाजार में तेजी का संकेत मिलता है, वहीं से खरीदारी बचकर निकालकर देश के दूसरे हिस्सों में कीमत थामने की कोशिश की जा रही है।

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

देशभर के प्याज बाजार पर पड़ता है नासिक की मंडियों की बात का असर

रेटिमीटिफर यानी सी-डेट को भारत की स्वदेशी दूरसंचार तकनीक को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रस्तुत करने वाला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने वाला है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री

सिर्फ जमीन व शेयर ही नहीं, यहां भी निवेश कर रहे हैं अमीर भारतीय

भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लंबे समय से यह लोग बेहतर रिटर्न के लिए पारंपरिक रूप से शेयर, स्थानीय आय और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निवेश करते आ रहे हैं। इस बीच कंसल्टेंट शेयर देव वाली फर्म-जूलियस वेयर और अमेरिट यंग (इंडाव) ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अब अमीर भारतीय बेहतर रिटर्न के लिए शेयरों और रियल एस्टेट पर निवेश नहीं हैं। अब अमीर भारतीय अपना 40-45% निवेश आय विस्फोट में कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर भारतीय कौन से क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं...



प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अमीर अब ज्यादा रिटर्न पाने के लिए प्राइवेट इक्विटी (पीई) और वेंचर कैपिटल (वीसी) फंड में निवेश कर रहे हैं। इसमें उनके वैकल्पिक निवेश का 10-20 प्रतिशत हिस्सा जा रहा है। यह पीई-वीसी फंड टेक्नोलॉजी, हेल्थटेक, नौकरशाही, ऊर्जा, उपभोक्ता कारोबार और बुनियादी वैश्विक रियल एस्टेट एप्लिकेशन में निवेश करते हैं। इससे अमीर भारतीयों को ज्यादा रणनीतिक भागीदारी और शुरुआती चरण में वैल्यू बढ़ाने में मौकों तक पहुंच मिलती है।



रिट-इन्विट
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीर परिवार पीई-वीसी और प्राइवेट इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं।



प्राइवेट क्रेडिट
प्राइवेट क्रेडिट एक और ऐसा क्षेत्र है जो अमीर लोगों का ध्यान खींच रहा है। देश में जैसे-जैसे पूंजी की मांग बढ़ रही है, बड़े परिवारों और आर्थिक या अमीर भारतीय परिवार प्राइवेट क्रेडिट बाजार में निवेश कर रहे हैं।



भारत में बड़े वैकल्पिक संयंत्र बाजार का आकार अनुमानित 400 अरब डॉलर है। इसमें वैश्वीकृत वैकल्पिक निवेश फंड (एआइएफए) की हिस्सेदारी 156 अरब डॉलर है। बाकी हिस्सा रिट, प्राइवेट इक्विटी और गैर-एलपीडी और 7.2 लाख टन एलएनपीजी का आयात किया



7.2 लाख टन एलएनपीजी का आयात किया है, जो जुलाई में 7.5 लाख टन था। कभी भारत का सबसे बड़ा एलएनपीजी आपूर्तिकर्ता रहे कार्गो से इस वर्ष अमेरिका में आयात शुरू रहा था। खाड़ी देशों से भारत के एलएनपीजी और एलएनपीजी आयात में तेजी से गिरावट आई है। इसका कारण ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बाद होमिंग जलडमरूमध्य का प्रभाव रूप से बंद होना है। गैस के लिए एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, जिससे खाड़ी देश प्रमुख उपभोक्ताओं को निर्यात करते हैं।



वैकल्पिक निवेश में है ज्यादा जोखिम
विशेषज्ञों का कहना है कि पीई-वीसी और प्राइवेट क्रेडिट जैसे वैकल्पिक निवेश क्षेत्रों में ज्यादा जोखिम होता है और कई बार निवेशकों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। इससे अलग, निवेशकों को राशि पुनः के लिए वही तक उतारना भी करना पड़ता है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि निवेश के विफल होने बहुत जटिल हो सकता है। इस कारण परिवारों और निवेशकों को पीई-वीसी, रियल एस्टेट, डेज फंड, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, टेक्नोलॉजी और दूसरी वैकल्पिक संस्थाओं का मूल्यांकन करना पड़ता है। इन सभी का अपना-अपना जोखिम प्रोफाइल और हानि जान-पड़ताल की जरूरत होती है।



सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा आरआरबी का शुद्ध लाभ

नई दिल्ली, आइएएस: बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का शुद्ध लाभ 10,176 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 2024-25 में 6,820 करोड़ रुपये था।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरआरबी के सकल लाभ-परफॉर्मिंग एस्टेट (जीएनपीए) और नेट लाभ-परफॉर्मिंग एस्टेट्स क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार हुआ है। सभी 28 आरआरबी का कुल कारोबार 13.5 लाख करोड़ रुपये की पाठ कर गया है। आरआरबी ने अपने क्रेडिट-डिफॉल्ट अनुपात में भी वृद्धि की है, जो 75.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया ने आरआरबी से कहा कि वे अपना अच्छा वित्तीय प्रदर्शन बनाए रखें और आखिरी छोर तक क्रेडिट पहुंचें और मजबूत करें।

ट्रेनों के पार्सल कोच में अब भेजे जा सकेंगे इत्र और परफ्यूम

जागरण संवाददाता • प्रयागराज

जलनगरी श्रेणी में होने के कारण अब तक इन्की लॉजिंग पर या प्रतिबंध

21 अगस्त को पूरे देश में लागू कर दी गई नई व्यवस्था

उत्सी नीतिगत प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए रेल डिपार्टमेंट के तहत अपने वाले परफ्यूमरी उत्पादों की भी शामिल कर लिया गया है। इस फैसले से इत्र, कार्मिस्टिक और पर्सनल केयर उद्योग से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे ट्रेनों में कम समय में लाभ पहुंचा सकेंगे। रेलवे बोर्ड की निदेशिका (पेट्ट मॉडेल) प्रतीति पाने के बादवा कि सुरक्षा के सख्त नियम लागू रहेंगे और परफ्यूमरी उत्पादों की लॉजिंग रेलवे प्रशासन को सीधी निगरानी में होगी।

भारतीय रेल से अब इत्र, डिओडोरेंट और सेंट जैसी परफ्यूमरी उत्पादों की देशभर में कहीं भी भेजा जा सकेगा।

इस स्थानीय स्तर पर एक शहर से दूसरे शहर भेजना आसान हो गया है। रेलवे बोर्ड ने पार्सल ट्रेनों के लॉजिंग पार्सल स्पेस (एसएसएलआर और बीपी कोच) में परफ्यूमरी उत्पादों की लॉजिंग को औपचारिक मंजूरी दे दी है। 21 अगस्त को सभी लाइन रेलवे के सहाराबंधकों को डेट्ट मॉडेलिंग स्कूल पर जारी कर नीतिगत नियमों में संशोधन के निर्देश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू कर दिया गया है।

इससे पहले रेलवे ने लॉजिंग कोचों में लिथियम-आयन बैटरी वाले उपकरणों को लॉजिंग से हटाकर अनुमति दी थी।

इससे पहले रेलवे ने लॉजिंग कोचों में लिथियम-आयन बैटरी वाले उपकरणों को लॉजिंग से हटाकर अनुमति दी थी।

ताक पर औचित्य

इससे बड़ी विवर्धना क्या होगी कि जो कानून या नियम-कायदे कभी आपात स्थिति या बहुत जरूरी होने पर ही प्रयोग किए जाने के लिए बनाए गए होंगे, उन्हें कोई बार कुछ खास लोगों को विशेष सुविधा मुहैया कराने का औचित्य बना लिया जाता है। यह एक तरह से किसी कानून का दुरुपयोग है और जब लगातार ऐसा होता है, तो सवाल उठता है कि सरकार नागरिकों के प्रति किसी कानून को बरतने के मामले में अपने स्तर से भी बेपरवाह करती है। वरना क्या वजह है कि जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए किसी सजायाफता को सिर्फ इसलिए बार-बार किसी कानून का लाभ दिया जाता है कि वह ऊँची रसूल वाला है या फिर उसकी खासी राजनीतिक पीठ है? गौरतलब है कि हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर इक्कीस दिन की फरलो दी गई है। यानी इस सुविधा के मिलने के बाद फिर से राम रहीम रोकतक स्थित सुनारिया जेल से बाहर निकल कर अपने आश्रम में रहेगा। इससे पहले भी उसे बारह बार पैरोल और पांच बार फरलो की सुविधा मिल चुकी है। ऐसा लगता है कि राम रहीम अपनी सजा को सिर्फ औपचारिकता भर के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक काट रहा है और उसे जब जरूरत पड़ती है, वह किसी न किसी बहाने जेल से बाहर आता का रस्ता बना लेता है।

सवाल है कि जिन नियम-कायदों के तहत राम रहीम को इस तरह की छूट बार-बार दी जा रही है, क्या सरकार यह दावा करती है कि स्थिति में है कि इस मामले में वह पूरी तरह तटस्थ और न्याय के तकाजे के मुताबिक काम कर रही है। बलाकार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में जिस व्यक्ति को सजा हुई, उसे लेकर इस स्तर पर जाकर नरमी बरतने का आखिर क्या कारण है? इस पर विपक्षी दलों और अनेक सामाजिक संगठनों की ओर से तीखी आपत्ति और विरोध जाहिर किए जाने पर सरकार की सफाई है कि राम रहीम को इस तरह की शिर्दाई नियमों के तहत दी जाती है। क्या सरकार गंभीर अपराधों की सजा काटने वाले अन्य लोगों के प्रति भी समान मानकों के तहत ऐसा ही रुख अपनानी है? फिर किसी भी कैदी को छूट दी जाती है तो रवैया दिखाने की क्या वजह हो सकती है कि पिछले दस साल में उसे सत्रह बार अलग-अलग कारणों से कभी पैरोल पर, तो तभी पैरोल पर जेल से बाहर आना समय सुविधाजनक तरीके से काटती की छूट दी जाती है?

यों राम रहीम को इस तरह जेल से बाहर रहने की सुविधा मुहैया कराते हुए शायद केवल उसकी जरूरतों का ही ध्यान रखा जा रहा है। मगर एक विचित्र संयोग यह भी देखा गया है कि जब भी उसके प्रभाव क्षेत्र में नुसान होने वाले होते हैं, तब आमतौर पर उसे खासी अवधि के लिए पैरोल या फिर फरलो की सुविधा मिल जाती है। फिलहाल पंजाब में विधानसभा चुनावों का समय करीब है और कई उत्तरी राज्यों सहित हरियाणा तथा पंजाब में राम रहीम के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही ऐसे आरोप लगाए रहे हैं कि राम रहीम को दरअसल चुनावी लोग उठाने के मकसद से बार-बार जेल से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है। सरकार को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम रहीम के प्रति इस तरह उदारता बरतने के क्रम में कानून की मनमानी व्याख्या करने की वजह से न्याय की अवधारणा को किस स्तर पर चोट पहुंच रही है।

जानलेवा शोर

देश में वायु प्रदूषण की तरह तेज आवाज का शोर भी गंभीर समस्या बन गया है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बे तक ध्वनि प्रदूषण की जग में हैं। इससे मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। लगातार आत्यधिक शोर के संपर्क में रहने से उत्पन्न रक्तचाप, अग्निदा, मानसिक तनाव, बेचारापन और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई दफा इसके तात्कालिक एवं गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते सोमवार को सामने आई, जब सड़क पर तेज आवाज में बज रहे डीजे के पास से गुजरते वक्ता साठ वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ जाने से मौत हो गई। सवाल है कि क्या ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कानून में सख्त प्रावधान हैं, तो फिर सार्वजनिक स्थलों पर बहुत तेज आवाज में डीजे बजाया या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति क्यों और कैसे दी जाती है? अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती?

गौरतलब है कि देश में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) अधिनियम के तहत विभिन्न स्थलों पर ध्वनि के स्तर की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर इएके सेंकितक लाई हैं। भी प्रावधान हैं। कई जगह सड़कों के आसपास के रहवासी इलाकों को आधिकांशिक तौर पर वाहनों के लिए ध्वनि निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए विशेष यंत्र लगाए गए हैं। मगर इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद तेज आवाज के शोर पर लगाम नहीं लगा पा रही है। जाहिर है कि इसके लिए संबंधित अधिकारों की लापरवाही ही जिम्मेदार है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को तो बहुत मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन ऐसी ही गंभीरता सड़कों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने में जरूर नहीं आती है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाने से अगर किसी की जान चली जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए कि शासिक कार्यों में कानून बना देने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था में सुधार तभी हो पाता है, जब उसे सख्ती से लागू किया जाए।

हड़ियों की कमजोरी से बढ़ता मनोभ्रंश

भारत में मनोभ्रंश की बीमारी से एक करोड़ से अधिक लोग पीड़ित हैं। यह बीमारी भले मस्तिक और स्मरण शक्ति से जुड़ी है, लेकिन इसका एक कारण हड़ियों का कमजोर होना भी है।

पुष्परजन

तकनीक के विकास और विलासितापूर्ण जीवनशैली के साथ-साथ डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश की बीमारी का संकेत भी बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में इस बीमारी से एक करोड़ से अधिक लोग पीड़ित हैं, जबकि हरके लक्ष्यों वाले लोगों की संख्या 2.4 करोड़ से ज्यादा है। मुख्य रूप से सात वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसकी चपेट में आते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2036 तक भारत में यह संख्या बढ़कर लगभग 1.69 करोड़ हो सकती है। यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में और वृद्धि उम्रवांकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखी गई है। यह बीमारी भले ही मस्तिष्क और स्मरण शक्ति से जुड़ी है, लेकिन इसका कारण हड़ियों का कमजोर होना है। आज के दौर में शारीरिक गतिविधियों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिससे हड़ियों की रेत भी कमजोर पड़ने लगी है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को चलने-फिरने में दिक्कत के साथ मनोभ्रंश की समस्या भी घेरने लगी है।

मानव शरीर की हड़ियों और दिमाग की रेत के बीच का संबंध शारीरिक सुरक्षा से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका संकेत 1800 के दशक में तब मिला, जब फ्रांसीसी पैथोलॉजिस्ट जॉन-मार्टिन चाकोटे ने हड़ियों में बने हुए हार्मोन 'ऑस्टियोकेल्सिन' और शारीरिक कार्यों में इसकी भूमिका के बारे में बेहतर समझ विकसित की थी। यह हार्मोन 'ऑस्टियोक्लास्ट' से बना है, जो हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। यह हड्डी से खून में मिल जाता है और रक्त शर्करा को व्यवस्थित करने तथा 'स्टेरोइड्स' और 'स्ट्रेन' हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो व्यायाम के दौरान हड़ियों के काम करने के लिए जरूरी होता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, 'ऑस्टियोकेल्सिन' हार्मोन चिंता एवं अवसाद को कम करता है और हमें किसी बात को याद रखने में मदद करता है। यह हार्मोन बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके दिमाग को विकसित करना शुरू करता है। यह मां के शरीर में बना है और गर्भवती के जिएर विकास हो रहे श्रुत तक पहुंचता है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि बुढ़ाई इसका तो तरह बूढ़े लोगों को भी वास्तविकता की समस्या होती है। परीक्षण के दौरान अंतराह्र माह के एक बूढ़े को दोबारा पानी के टैंक में छोड़ दिया गया। चूहा की उम्र के हड़ियों से उसे बूढ़ा कहा जा सकता है। वह पानी के नीचे एक ढांचे को हिलाने की कोशिश करता है, जिस पर चढ़ सक, लेकिन उसे पता नहीं आता कि वह कहाँ है। इसी तरह के टैंक में डाले



गए अन्य युवा चूहे को उस ढांचे को तलाशने में कोई दिक्कत नहीं होती, जिसका इस्तेमाल उसने एक दिन पहले किया था। वैज्ञानिक बूढ़े चूहे को 'ऑस्टियोकेल्सिन' की एक खुराक देते हैं, जिससे उसकी यादवस्त बेहतर हो जाती है और वह उस ढांचे को ढूंढ़ लेता है।

जब हड़ियां कमजोर हो जाती हैं, तो हड्डी की टुकड़ों पर भी उनका टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में अगर सोवने-समझने एवं सुनने की क्षमता को बनाए रखना है और हड़ियों को टूटने से बचना है, तो उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। हड़ियों और दिमाग के बीच के परस्पर संबंधों को मजबूत बनाए रखने का सबसे असरदार और आसान तरीका है, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। देश में मनोभ्रंश के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर भी व्यापक प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम और अभियान शुरू करने होंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड्डी एवं मानसिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करनी होंगी और प्रभावी इलाज के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करने होंगे।

वैज्ञानिकों ने एक और बात जानी कि चूहे में लगभग नौ माह की उम्र में तथा महिलाओं में तीस साल और पुरुषों में पचास साल की उम्र से

शिक्षण का दायरा

निधि गोयल

आजकल कुछ ऐसा दौर चल पड़ा है, जिसमें बच्चों की प्रतिभा माता-पिता को सिर्फ उनकी पढ़ाई में ही दिखाई दे और अन्य गतिविधियों में उन्हें लगता है कि समय खराब हो रहा है। ऐसी सोच हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ही जीवन को सही तरीके से जीने पर भी प्रभाव डाल सकती है। सच यह है कि केवल किताबों तक सीमित रहने पर बच्चे का सर्गुण विकास नहीं हो पाता है। पढ़ाई के साथ-साथ खेल, तुल, संगीत, चित्रकारी, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों भी बच्चों के विकास को निखारने में अहम भूमिका निभाती हैं।

अक्सर देखने में आता है कि बच्चा पढ़ाई के अलावा जब अन्य गतिविधियों में शामिल होता है, तो तभी उसकी छिपी प्रतिभा बाहर निकलती है। कुछ बच्चे पढ़ाई में औसत होते हैं, लेकिन खेल, कला, संगीत या किसी अन्य क्षेत्र में जायदा प्रदर्शन करते हैं। उनकी क्षमता तभी सामने आती है, जब उन्हें तबखुदा खंचे की पढ़ाई से बाहर निकलना होता है या उन्हें निकलने का मौका मिलता है। सच यह है कि हर बच्चे की अलग रूचि होती है और अगर उसमें खुद की अभिव्यक्ति करने का मौका मिले, तो उसके अनुसार उन्हें कुछ नया सीखने की मिलाता है। अपनी रूचि की गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। जबकि सिर्फ घर में बैठ कर बच्चा पढ़ता रहता है, तो उसका होसला और आत्मविश्वास कुछ बड़ा डगमगाते लगता है। वहीं इससे उत्तर कुछ और सीखना का मौका मिलता है, तो इससे उसके मन में विश्वास पैदा होता है कि वह किसी से कम नहीं है। जब हम कुछ सीखते हैं, तो हमारी कल्पनाशक्ति और रचनात्मक सोच में इजाफा होता है। बेसी हद चित्रकारी, संगीत, लेखन आदि सीखते हैं, तो हमारा दिमाग अलग तरह से काम करता है, तो हमारा से हटकर कुछ नया सीखते हैं और उस पर काम करते हैं। साथ ही समस्या को अलग नजरिए से देखना और उसका समाधान खोजना सीखते हैं।

आज एकतरफा परिवार का चलन है, जिसमें आमतौर पर एक या दो बच्चे ही घर में होते हैं। ऐसे में बच्चों को अकेले रहने की आदत डाल कर दी जाती है कि वे किसी के साथ कुछ भी साझा करने से कतरते हैं। उनके बच्चों से मिलना-जुलना, हंसना-बोलना अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए घर से स्कूल या कलेज- बस यही रास्ता है। जबकि उन्हें अन्य गतिविधियों में जरूर प्रेरणा की कोशिश होनी चाहिए। इससे बच्चे को समझ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वे दूसरों की बात सुनना, अपनी जिम्मेदारी और बीत-हराह की उत्तरदायकता सीखते हैं। आजकल बड़ी संख्या में बच्चे भी अवसाद के शिकार हो रहे हैं, तो उनका तनाव कम करने में हमारी जिम्मेदारी है। खेलकूद और मनोरंजक गतिविधियां उनके तनाव को कम करती हैं

दुनिया मेरे आगे

पढ़ाई बच्चों को ज्ञान देती है, लेकिन किताबों से बाहर की दुनिया उन्हें आत्मविश्वास, रचनात्मकता, अनुशासन, सामूहिकता और जीवन के ज़रूरी खलक सिखाती है। इसलिए बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है।

उम्र में आगे निकलने की चाह में कुछ बच्चे अपना जीवन खल कर रहे हैं, ऐसी बातों की उनके मन में विकसित न होने दिया जाए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पढ़ाई और अन्य गतिविधियों को सही ढंग से जोड़ना न बन जाए। उन्हें अपनी जीवन की सरल बनाना है, न कि उनका मुश्किल कर दे उससे हार मान जाए। पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने पर उनका दिमाग और महसूस करने में मदद करता है। सच यह है कि पढ़ाई बच्चों को ज्ञान देती है, लेकिन किताबों से बाहर की दुनिया उन्हें आत्मविश्वास, रचनात्मकता, अनुशासन, सामूहिकता और जीवन के ज़रूरी खलक सिखाती है। इसलिए बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना बेहतर जरूरी है।

कड़वी होती चीनी

टोल में बीस फीसद एथेनाल मिश्रण को पहल से खाद्य महंगाई के साथ देश में चीनी की किल्लत बढ़ गई है। यह गंभीर स्थिति है।

बीक और खाद्य चीनी की कीमतों में भारी उछाल आया, तो सरकार को त्योहारों से पहले कीमतों को स्थिर करने के लिए निर्यात रोकना पड़ा और कच्ची चीनी के आयात की अनुमति देनी पड़ी। आलोचकों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। मगर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। तब पर बचत के लिए विदेशी मुद्रा का व्यापार करना और फिर संभावित रूप से रसी पैरों को बचाने के लिए खरीदना, यह कौन सी बुद्धिमानी हुई? एथेनाल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल हुआ। मूलतः चीनी का उत्पादन कम होने लगा। अक्सर अमरत तक देश में चीनी की औसत खुराक कीमत 50 से 55 रुपये प्रति किलो थी। एक सप्ताह पहले 45 रुपये प्रति किलो थी। यानी सालाना करीब 13 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल चीनी का नाम लगातार बढ़ रहा है। इसका असर यह होगा कि चीनी से बने वाली चीजें अब थोड़े-थोड़े महंगी होती जाएंगी। आखिर इन परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है?

- जग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

सजगता ही बचाव

दिल्ली में खानदूत युवा एकाग्रता संक्रमण के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। पिछले दिनों एक दिन में सी से ज्यादा गुगु मामले आए। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते वर्ष इती अवधि में 229 मामले दर्ज हुए थे। यानी इस वर्ष संक्रमण के मामले करीब सात-आठ गुना अधिक बढ़ गए हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि संक्रमण को केवल मौसमी बीमारी मान कर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। बुढ़ाई, छोटे बच्चे, गर्भवती

हृदय बड़क दुर्घटनाएं गंभीर समस्या बन गई हैं। देश में प्रतिवर्ष पांच लाख दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इनमें सबसे घाली की संख्या का बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। खराब सड़कों, निर्माण में गलत बनावट और गड़बड़ की वजह से रोज लोगों की जान जा रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए संबंधित निर्माण एजेंसियों से जवाब-दायक किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा विभाग की कमियों को रोकना और

महंगाई की आग

मेरिका-ईरान युद्ध का असर अब दिखने लगा है। महंगाई दिनों-दिन बढ़ रही है। आसमान छूते भाव से लोग मुश्किल में हैं। चीनी महंगी हो रही है। प्याज का दाम भी बढ़ते हुए 60 से 70 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। आखिर इतनी महंगाई में नागरिक कैसे पर्व-त्योहार मना पाएंगे। टोल-डीलर के बावजूद चीनी और प्याज का महंगा होना गंभीर बात है। मगर इसी के साथ जीवन उपयोगी अन्य सामग्री की महंगी होती चली गई है, तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को इस महंगाई को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। कुछ कारगर रणनीति बनाकर होगी। आवश्यक चीजों के आसमान छूते भाव उलाने को बेहतर चुन है निजीकता आम काम का सीमित है। अक्सरों को बात है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उसी गति से लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। गैरगार के नए आवरण भी सामने नहीं आ रहे।

- योगेश जोशी, बड़वाह

सरकारी स्कूलों से हमें ज्यादा उम्मीद

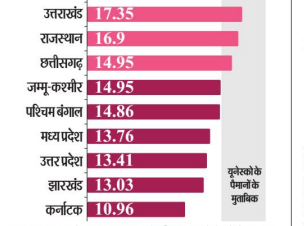
हमने शिक्षा में लंबा सफर तय किया है और अभी बहुत आगे जाना है। आजादी के बाद आबादी चार गुना हो गई है, तो स्कूलों की संख्या भी करीब दस गुना बढ़ी है। इधर, कुछ राज्यों में स्कूल सुधार के लिए प्रदर्शन हुए हैं, पर उनका हाल राज्य सरकारों की जानकारी है। आज कैसे हैं सरकारी स्कूल और सुधार की जरूरत कहाँ सबसे ज्यादा है? पेश है **रूपंजल चौहान और प्रज्ञा श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट...**



देश के कुछ हिस्सों में हुए छात्र प्रदर्शनों में सरकारी स्कूल संबंधी जरूरी सुविधाओं की मांग जोर-शोर से सुनी गई है। इसका नतीजा है कि अनेक राज्यों में स्कूल सुधार के कार्यों में तेजी आती दिख रही है। वहीं वहाँ भी बड़ी संख्या में निजी स्कूल खुले हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का संरक्षण आज भी बहुत जरूरी है। आंकड़े बताते हैं, साल 2018-19 और 2025-26 के बीच लगभग 84,000 सरकारी स्कूलों का निर्माण हुआ। लेकिन 2018-19 और 2025-26 के बीच लगभग 84,000 सरकारी स्कूलों का निर्माण हुआ। लेकिन 2018-19 और 2025-26 के बीच लगभग 84,000 सरकारी स्कूलों का निर्माण हुआ।

66% ग्रामीण बच्चे सरकारी स्कूलों से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं।
30% शहरी बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।
69% स्कूल सरकारी हैं, जिनमें 50% से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं।

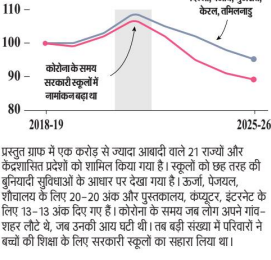
केवल चार राज्यों का शिक्षा खर्च सराहनीय
राज्य सरकारों ने शिक्षा पर जोर दिया है, फिर भी अपने कुल व्यय में से कुछ ही राज्य ठीकठा खर्च कर रहे हैं। (आंकड़े प्रतिशत में)



साल 2018-19 से साल 2025-26 के बीच सरकारी ने जो शिक्षा पर खर्च किया है, उसका औसत प्रतिशत यहां दिया गया है।

■ सामान्य सरकारी स्कूलों में प्रति वर्ष 5,000 रुपये से भी कम में शिक्षा खर्च है।
■ निजी में वार्षिक खर्च न्यूनतम 25,000 रुपये।
■ देश के सबसे महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ने का वार्षिक खर्च 31 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

अच्छे स्कूल वाले राज्यों में भी घटा नामांकन
अनेक राज्यों में, जहां सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन वहां भी धीरे-धीरे नामांकन घटता जा रहा है...



प्रस्तुत ग्राफ में एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। स्कूलों को छह तरह की बुनियादी सुविधाओं के आधार पर देखा गया है। ऊर्जा, पेयजल, शौचालय के लिए 20-20 अंक और पर्यावरण, कम्प्यूटर, इंटरनेट के लिए 13-13 अंक दिए गए हैं। कोरोंन के समय जब लोग अपने गांव-शहर छोड़ते थे, जब उन्होंने आधी कोटी की। तब बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों का सहारा लिया था।

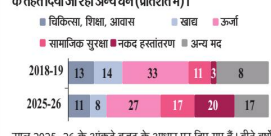
आज भी वही सच है कि देश के कुल स्कूलों में से लगभग तीन-चौथाई सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त हैं और वे भारत की शिक्षा तंत्र की रीढ़ हैं। पिछले दशक में ही उन्होंने हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत से घटकर तीन-चौथाई हो गई है।

यहां नीति आयोग की रिपोर्ट सही दशा करती है। मायमिक्सिटर पर डीएआरटी में तीव्र रुढ़ि यह बताती है कि छात्र स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, पर ओपेन स्कूलों का यह है, जिससे शिक्षा का उर्ध्व पुरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

...और निजी स्कूलों पर बढ़ रहा भरोसा
मिट दवा एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विरुद्ध के आधारे के आधार पर पाया गया कि जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ज्यादा काम की जरूरत है। पिछले दशक में भी निजी स्कूल खुल रहे हैं, उन पर लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। सफल निजी स्कूलों से भी सरकारी स्कूलों को सीखना चाहिए। भारत में निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से बेहतर

प्रदर्शन क्यों करते हैं? वे शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नई रणनीतियां अपनाते हैं। बेहतर प्रबंधन करते हैं। शिक्षकों की महत्ता को और छात्रों से भी महत्ता करते हैं। छात्र रहे तुलनात्मक रूप से निजी स्कूल के शिक्षकों का समय भर-अवकाशिक कार्य में काम बर्बाद होता है। निजी स्कूलों में शिक्षक काम चलायती लेते हैं। पेशेवर दम से पढ़ाते हैं। परीक्षा परीक्षा की समीक्षा करते हैं और उसमें अभिभावकों को भी नियमित रूप से शामिल करते हैं। आम तौर पर देखा गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में ही पढ़ने जाते हैं।

शिक्षा का बजट बढ़ाने की जरूरत
अपने देश में विभिन्न क्षेत्रों को दी जा रही संस्थिती और कार्यक्रमों के तहत दिया जा रहा अन्य धन (प्रतिशत में)।



साल 2025-26 के आंकड़े बजट के आधार पर दिए गए हैं। वीते वहाँ में शिक्षा पर खर्च बोझ बढ़ा है।

सुधार के कदम

संजगता: सक्रिय हों सामाजिक संगठन

गांव के स्तर पर ही ग्रामीणों को स्थानीय स्कूल सुधार के लिए संलग्न होना पड़ेगा। शिक्षकों की कमी को दूर करना, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारना और स्कूल के समग्र ढांचे में सुधार करना स्थानीय स्तर पर मिलकर अभिभावक या ग्रामीण भी सुधार सकते हैं। देश के राज्यों में जन स्वावलंबन से ही सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है।

संसाधन: सरकार बजट और सुविधाएं बढ़ाए

प्राथमिक सरकारी स्कूलों में पहले की तुलना में ज्यादा धन व संसाधन बढ़ रहा है। फिर भी देश में करीब 1,04,125 एलएन-शिक्षक विद्यार्थी में 33 लाख बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षकों को किंगडू बीस से बचाने के लिए भी बजट व संसाधन बढ़ाना जरूरी है। बुनियादी तौर पर स्कूलों में जो अप्रभाव है, उन्हें दुरु स्तर पर दूर किया जाना चाहिए।

संयोजन: कुशल शिक्षकों को दी जाए जिम्मेदारी

देश में एक करोड़ से अधिक प्राथमिक शिक्षक हैं, जिनमें 50.9% सरकारी स्कूलों में पदस्थ हैं। देश में करीब 10 लाख शिक्षक अभी भी प्रशिक्षित या कुशल नहीं हैं। सरकारी स्कूलों को पेशेवर दम से संचालित रखने की जरूरत है। शिक्षा विभाग और अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी सरकारी स्कूल उपयोग हवा में न रहे।

नकद धन वितरण पर लगातार बढ़ता खर्च

देश में कम से कम 12-14 राज्यों में केन्द्र शासित प्रदेशों ने किसी न किसी रूप में नकद हस्तान्तरण की घोषणा की है। नकद हस्तान्तरण का हिस्सा 2018-19 में मात्र 3% से बढ़कर 2025-26 में 20% हो गया है। वहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास पर संस्थिती व हस्तान्तरण का हिस्सा 13% से घटकर 11% हो गया है। लोग सामान्य जीवन शैली से बाहर जा रहे हैं।

निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में है। प्रधान रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 66 प्रतिशत छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सरकारी स्कूलों में अध्ययन के सुविधाओं, पर्यावरण, सुधार और शिक्षादायक स्कूलों व पाठ्यक्रम की गुणवत्ता जैसे बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि सरकारी शिक्षा अभी संभव नहीं है।

पूरे स्कूल शिक्षा सुनिश्चित करना करना है, इन सभी चीजों का समाधान किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर राजनीति और कोषिक कर्म की वजह से नहीं, पांच साल बाद बच्चा होगा इस्कोली नहीं। स्मार्टफोन व चतुर्थ क्रांति के लिए, किसी परिवार को स्मार्टफोन और इंटरनेट में निवेश करने के बिना प्रचार व प्रचारों पर जोर दिया है। स्मार्टफोन व चतुर्थ क्रांति के लिए, किसी परिवार को स्मार्टफोन और इंटरनेट में निवेश करने के बिना प्रचार व प्रचारों पर जोर दिया है।

सुकोकू: 83886 *कॉडन

खेलने का तरीका: दिमागी खेल और नवंबर की पहली है। ऊपर नीचे-नी खानों के नीचे खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 को संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पंक्ति दोनों में हर एक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएँ। साथ ही 3x3 के हर एक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहली का हल हम कर देंगे।

सुकोकू: 83885

5 4 8 6 7 1 9 3 2 1 3 5 7 9 6 4 8 9 7 6 4 3 2 5 1 6 1 6 5 7 4 3 8 2 9 4 3 2 1 9 8 5 7 6 7 8 9 2 5 6 1 3 4 3 5 1 4 6 2 9 8 7 8 2 4 9 1 7 3 6 5 6 9 7 3 8 5 4 1 2



पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

पं. रावसेन शर्मा
ज्योतिषशास्त्र

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

- English Editorials PDF with International Newspapers Editorials [35-40 pages]
- Hindi Editorials PDF
- Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International
[General & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world.
Asian, European & American

Hindi Newspapers

- 1) दैनिक जागरण
- 2) जनसत्ता
- 3) हरिभूमि
- 4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express

2. The Hindu

3. Business Line

4. Financial Express

5. Times of India

6. Hindustan Times

7. Economic Times

8. Live Mint

9. Business Standard

